भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2173
दिनांक 07.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पड़ोसी देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों का संरक्षण

2173. सुश्री सुष्मिता देवः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) विगत पाँच वर्षों में पड़ोसी देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हुई हिंसा, उत्पीड़न या योजनाबद्ध भेदभाव की घटनाओं का ब्यौरा क्या है**;**
(ख) ऐसी घटनाओं पर प्रतिक्रिया रूप में भारत द्वारा जारी किए गए किसी औपचारिक राजनयिक संचार, विरोध या कार्यवाही का ब्यौरा क्या है**;**
(ग) क्या सरकार ने इन देशों से राष्ट्रीयता या जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा **(1992)** के अनुरूप अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने का आग्रह किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;** और
(घ) पड़ोसी देशों के साथ अल्पसंख्यक सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों के समाधान के लिए क्या संस्थागत या द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं**?**

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क) से **(घ)** भारत सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सहित पड़ोसी देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा और अत्याचार की रिपोर्टों पर नियमित रूप से नजर रखती है।

पाकिस्तान के संबंध में, **2021** से, भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के समक्ष कम से कम **334** बड़ी घटनाओं को उठाया है और उससे अल्पसंख्यक समुदायों सहित उसके नागरिकों के प्रति उनके संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने और सांप्रदायिक हिंसा, अति पूर्वाग्रहों और धार्मिक असहिष्णुता को समाप्त करने का आग्रह किया है। कई अवसरों पर, भारत ने जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति और उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन को उजागर किया है।

बांग्लादेश के मामले में, **2021** से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कम से कम **3,582** घटनाएं दर्ज की गई हैं। भारत सरकार ने इस मामले पर अपनी चिंताओं को बांग्लादेश सरकार के साथ साझा किया

है जिसमें उच्चतम स्तर भी शामिल है, इस आशा के साथ कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी।

जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, **2021** में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बाद, अल्पसंख्यक समुदाय के **74** सदस्यों, मुख्य रूप से अफगान सिखों को भारत सरकार द्वारा 'ऑपरेशन देवी शक्ति' के तहत निकाला गया था। इसके अलावा, भारत सरकार ने **18** जून **2022** को काबुल में गुरुद्वारा दशमेश पिता साहिब श्री गोबिंद साहिब जी पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की थी जिसमें निर्दोष नागरिक आबादी को निशाना बनाया गया था।

भारत सरकार संबंधित सरकारों पर यह दबाव डालती रहती है कि अल्पसंख्यक समुदायों सहित सभी नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी उन पर है।

*****